

विनियोग संख्या 67 – भारत का उच्चतम न्यायालय
APPROPRIATION No. 67 - SUPREME COURT OF INDIA

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:				
प्रभारित—	Charged-				
मूल	Original	456,54,00	507,96,00	507,96,00	..
पूरक	Supplementary	51,42,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि Amount surrendered during the year					शून्य Nil

पूंजीगत:	Capital:				
प्रभारित—	Charged-				
मूल	Original	68,95,00	98,09,00	90,59,00	-7,50,00
पूरक	Supplementary	29,14,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि Amount surrendered during the year					7,50,00

टीका और टिप्पणियां

1. विनियोग के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹750.00 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹2914.00 लाख के पूरक विनियोग का 26 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 8 प्रतिशत थीं।

Notes and comments

1. In the capital section of the appropriation, the overall savings (₹ 750.00 lakhs) constituted 26 percent of the supplementary appropriation of ₹ 2914.00 lakhs obtained in December, 2024 and 8 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं—

Savings occurred under the following major head:-

कुल विनियोग
Total
appropriation

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4075"	Major Head "4075"				
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	6895.00	9059.00	9059.00	..
पू.	S.	2914.00			
पु.	R.	-750.00			

(I) "निदेशन एवं प्रशासन - सचिवालय सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत ₹ 6895.00 लाख के मूल विनियोग को ₹ 2914.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹ 9809.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो विक्रेताओं से बिल प्राप्त न होने के कारण ₹ 750.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रह गया।

(I) Under "Direction & Administration - Secretariat General Services" - the original appropriation of ₹ 6895.00 lakhs was augmented to ₹ 9809.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹ 2914.00 lakhs, which, however remained unutilized to the extent of ₹ 750.00 lakhs - due to non-receipt of bills from vendors.